Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

भोपाल जिले की भील जनजाति के विकास में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका और प्रभावशीलता का विश्लेषण

मनीष सोनी
शोधार्थी , आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल
हुदा फैज़
शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग, आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल

सारांश
भारत के सबसे बड़े अनुसूचित जनजातीय समुदायों में से एक भील जनजाति ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर उपेक्षित रही है। मध्य प्रदेश राज्य में भील जनजाति की संख्या सर्वाधिक है—राज्य की कुल जनजातियों में भीलों का प्रतिशत 37.7% है। प्रस्तुत अध्ययन भोपाल जिले के संदर्भ में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की भील जनजाति के विकास में भूमिका एवं प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। अध्ययन में पाया गया कि यद्यपि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं—जिनमें जननी सुरक्षा योजना (JSY), PVTG आहार अनुदान योजना, एकीकृत आवासीय छात्रावास योजना, वन धन योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रमुख हैं—तथापि इन योजनाओं की पहुँच, जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन में व्यापक अंतराल विद्यमान हैं। अध्ययन के अनुसार 65.7% भील महिलाएँ इन योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि भौगोलिक दुर्गमता, शिक्षा का निम्न स्तर, प्रशासनिक अक्षमता एवं सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधक हैं। शोध-पत्र में भोपाल जिले के संदर्भ में योजनाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ एवं समावेशी बनाने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द: भील जनजाति, कल्याणकारी योजनाएँ, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, भोपाल जिला, योजना प्रभावशीलता

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

भारत की जनजातीय आबादी, जिसमें 705 से अधिक विभिन्न समूहों के 10.42 करोड़ लोग शामिल हैं, प्रायः दुर्गम एवं विकट भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करती है। इन समुदायों के उत्थान के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की हैं। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,53,16,784 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है—मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों में भीलों की संख्या 37.7 प्रतिशत है।

1.2 समस्या का निरूपण

स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। तथापि, जनजातीय विकास की प्रक्रिया अत्यंत धीमी रही है। विभिन्न संघीय एवं राज्य कानूनों के तहत जनजातियों को अनेक अधिकार एवं रियायतें दी गई हैं, परंतु क्रियान्वयन एजेंसियों की अज्ञानता एवं उदासीनता के कारण इन्हें लाभों से वंचित रखा जा रहा है। विकास कार्यक्रमों को संचालित करने वाली क्रियान्वयन एजेंसियों की बहुलता ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है।

इस पृष्ठभूमि में भोपाल जिले—जो मध्य प्रदेश की राजधानी है—के संदर्भ में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका एवं प्रभावशीलता का विश्लेषण अत्यंत प्रासंगिक एवं आवश्यक है।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

1. भोपाल जिले में भील जनजाति के लिए संचालित प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहचान करना।
2. इन योजनाओं की पहुँच एवं लाभांवित आबादी का आकलन करना।
3. योजनाओं के सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति) में योगदान का विश्लेषण करना।
4. योजनाओं के आर्थिक विकास (आय, रोजगार, आजीविका) में योगदान का विश्लेषण करना।
5. योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधक कारकों की पहचान करना।
6. योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

2. भोपाल जिले में भील जनजाति हेतु संचालित प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ

मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा भील जनजाति के कल्याण हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी हित से जुड़ी 9 सरकारी योजनाओं एवं महिला बाल विकास विभाग की एक सरकारी योजना को अगले पाँच वर्ष (2030-31) तक जारी रखने हेतु 7,133.17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन योजनाओं का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो रहा था, अब ये सभी योजनाएँ मार्च 2031 तक जारी रहेंगी।

तालिका 1: भोपाल जिले में भील जनजाति हेतु प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	उद्देश्य	लाभार्थी	वित्तीय परिव्यय
1	जननी सुरक्षा योजना (JSY)	2005	संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना	गर्भवती महिलाएँ (BPL परिवार)	केन्द्र प्रायोजित
2	PVTG आहार अनुदान योजना	-	विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों की महिला मुखियाओं को पोषण सहायता	PVTG परिवारों की महिला मुखिया	2,350 करोड़ रुपए

3	एकीकृत आवासीय छात्रावास योजना	-	जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा सुविधाएँ	अनुसूचित जनजाति के छात्र	1,703.15 करोड़ रुपए
4	वन धन विकास योजना (PMVDY)	-	लघु वनोपज पर केंद्रित आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले केंद्र स्थापित करना	वनोपज संग्राहक एवं कारीगर	केन्द्र प्रायोजित
5	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	2024	सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका में सुधार	63,000+ जनजातीय गाँव	79,156 करोड़ रुपए
6	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	-	कक्षा 1-10 के जनजातीय छात्रों को शैक्षिक सहायता	अनुसूचित जनजाति के छात्र	राज्य/केन्द्र प्रायोजित
7	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	-	उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता	अनुसूचित जनजाति के छात्र	राज्य/केन्द्र प्रायोजित
8	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना	-	व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा हेतु ₹10 लाख तक ऋण	अनुसूचित जनजाति के छात्र	राज्य प्रायोजित
9	मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना	-	दलित एवं आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना	अनुसूचित जाति/जनजाति	राज्य प्रायोजित

(स्रोत: विभिन्न सरकारी विभागों की रिपोर्टों एवं प्रकाशनों के आधार पर)

3. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव एवं प्रभावशीलता: एक विश्लेषण

3.1 स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभाव

3.1.1 जननी सुरक्षा योजना (JSY) का प्रभाव

जननी सुरक्षा योजना (JSY)—जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है—का प्रारंभ वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। अध्ययनों से पता चला है कि JSY के कारण जनजातीय समुदायों में संस्थागत प्रसव के अनुपात में सुधार हुआ है। तथापि, अधिकांश महिलाओं को प्रसव-पश्चात् अनुवर्ती जाँच या जाँच-पड़ताल नहीं मिलती। केवल 42% शिशुओं को जीवन के प्रथम माह के दौरान कोई जाँच या स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दौरा प्राप्त हुआ। भील जनजाति के बीच चिकित्सकीय रूप से स्वीकार्य नवजात प्रथाएँ—जैसे शीघ्र सुखाना एवं लपेटना, शीघ्र स्तनपान आरंभ एवं विशेष स्तनपान—प्रचलन में नहीं हैं।

3.1.2 स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में बाधाएँ

भौगोलिक दुर्गमता, कम स्वास्थ्य साक्षरता और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के कम उपयोग जैसे कारकों के कारण भील महिलाओं के बीच स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच अभी भी बाधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी नीतियों की शुरुआत के बावजूद, भील महिलाओं को मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल का सामना करना पड़ रहा है।

3.2 शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव

3.2.1 छात्रवृत्ति एवं आवासीय सुविधाओं का प्रभाव

शासकीय छात्रवृत्ति योजनाओं एवं एकीकृत आवासीय छात्रावास योजना के कारण भील बच्चों की विद्यालय उपस्थिति में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान तथा समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु विभाग द्वारा योजनाओं का संचालन किया जाता है। तथापि, भील समाज में साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

3.3 आर्थिक विकास में प्रभाव

3.3.1 वन धन योजना का प्रभाव

वन धन विकास योजना (PMVDY) का उद्देश्य मुख्य रूप से आदिवासी जिलों में लघु वनोपज (MFP) पर केंद्रित आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले बहुउद्देश्यीय वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है। एक केंद्र 15 आदिवासी स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन करेगा, जिसमें प्रत्येक में 20 आदिवासी एनटीएफपी इकट्ठा करने वाले कारीगर होंगे। TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) इस योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3.3.2 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए इस अभियान का लक्ष्य आकांक्षी जिलों में 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों को 79,156 करोड़ रुपये के बजट से परिपूर्णता प्रदान करना है। अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से 25 प्रयासों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण कमियों को खत्म किया जाना है। इस अभियान में 30 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के 63,000 गाँव शामिल किए गए हैं, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा।

भोपाल जिले के संदर्भ में, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 63,077 घरों और 650 सरकारी संस्थानों तक ग्रिड आधारित बिजली पहुँचाने के लिए 366.72 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, जहाँ विद्युत लाइन नहीं पहुँच सकती, वहाँ 8,521 घरों को ऑफ ग्रिड सौर विद्युतीकरण योजना के तहत सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए 97 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

4. योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

4.1 जागरूकता एवं पहुँच

योजनाओं की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा संकेतक लाभार्थियों तक उनकी पहुँच एवं जागरूकता है। झाबुआ जिले में किए गए एक अध्ययन के अनुसार:

तालिका 2: सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता

प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
जागरूक (हाँ)	103	34.3%
अनजान (नहीं)	197	65.7%
कुल	**300**	**100.0%**

(स्रोत: Shodhganga अध्ययन, झाबुआ जिला)

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि ये हस्तक्षेप सभी जनजातीय आबादी को कवर नहीं कर पाए हैं। बहुमत (65.7%) भील महिलाएँ इन कार्यक्रमों से अनभिज्ञ थीं, अतः वे लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं।

तालिका 3: कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रकार के प्रति जागरूकता

प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
स्वयं सहायता समूह (SHG)	100	33.3%
उषाकिरण योजना	1	0.3%
वृद्धावस्था पेंशन योजना	1	0.3%
कोई प्रतिक्रिया नहीं	198	66.0%
कुल	**300**	**100.0%**

(स्रोत: Shodhganga अध्ययन, झाबुआ जिला)

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि बहुमत (66.0%) महिला उत्तरदाता अपने क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं/गतिविधियों का नाम नहीं बता सकीं। यह इंगित करता है कि इन कार्यक्रमों के बारे में प्रचार या उचित सूचना लक्ष्य समूहों तक नहीं पहुँच रही है।

4.2 भौगोलिक असमानताएँ

मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय (आदिवासी) बाहुल्य जिलों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और प्रशासनिक लेटलतीफी को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब आदिवासी जिलों में टेंडर और ठेकों को मंजूरी दे सकेंगे कलेक्टर। तथापि, भोपाल जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच योजनाओं की पहुँच में महत्वपूर्ण असमानता पाई जाती है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

4.3 प्रशासनिक चुनौतियाँ

योजनाओं की प्रभावशीलता में प्रमुख बाधाओं में शामिल हैं:

1. **क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव** - विभिन्न एजेंसियाँ अपने प्रयासों का समन्वय करने में असमर्थ हैं
2. **दीर्घकालिक कार्यक्रमों के पालन में विफलता**
3. **भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों की उपस्थिति**
4. **प्रशासनिक लेटलतीफी**

5. योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधक कारक

तालिका 4: योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधक प्रमुख कारक

क्र.सं.	बाधक कारक	विवरण	प्रभाव स्तर
1	जागरूकता का अभाव	65.7% भील महिलाएँ योजनाओं से अनभिज्ञ	अत्यधिक
2	भौगोलिक दुर्गमता	दूरस्थ क्षेत्रों में योजनाओं की पहुँच सीमित	अत्यधिक
3	शिक्षा का निम्न स्तर	साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम	उच्च
4	प्रशासनिक अक्षमता	समन्वय का अभाव, लेटलतीफी, भ्रष्टाचार	उच्च
5	सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ	पारंपरिक मान्यताएँ, आधुनिक प्रणाली के प्रति अविश्वास	मध्यम
6	आर्थिक कमजोरी	गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का उच्च अनुपात	उच्च
7	सूचना प्रसार में कमी	योजनाओं की जानकारी लक्ष्य समूहों तक नहीं पहुँच पाती	अत्यधिक

6. योजनाओं का तुलनात्मक प्रभाव विश्लेषण

तालिका 5: विभिन्न योजनाओं का तुलनात्मक प्रभाव मूल्यांकन

योजना	लक्षित क्षेत्र	पहुँच (%)	प्रभावशीलता स्कोर*	प्रमुख उपलब्धियाँ	प्रमुख चुनौतियाँ
जननी सुरक्षा योजना (JSY)	स्वास्थ्य	34-60%	6.5/10	संस्थागत प्रसव में वृद्धि	प्रसव-पश्चात् जाँच का अभाव
PVTG आहार अनुदान योजना	पोषण	सीमित	7/10	महिला मुखियाओं को ₹1,500/माह	केवल PVTG परिवारों तक सीमित
एकीकृत आवासीय छात्रावास योजना	शिक्षा	मध्यम	6/10	जनजातीय छात्रों को आवासीय सुविधा	छात्रावासों की संख्या अपर्याप्त

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

वन धन योजना	आजीविका	सीमित	5.5/10	वनोपज विपणन में सुधार	भोपाल जिले में सीमित पहुँच
धरती आबा अभियान	समग्र	प्रारंभिक	7.5/10	63,000+ गाँवों को कवर	अभी प्रारंभिक चरण में
छात्रवृत्ति योजनाएँ	शिक्षा	मध्यम	6/10	विद्यालय उपस्थिति में वृद्धि	राशि अपर्याप्त, विलंब

**प्रभावशीलता स्कोर: शोधकर्ता के आकलन पर आधारित (1-10 के पैमाने पर)*

7. निष्कर्ष एवं सुझाव

7.1 निष्कर्ष

प्रस्तुत विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

1. **योजनाओं की उपस्थिति सकारात्मक है** - भोपाल जिले में भील जनजाति के लिए अनेक केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी योजनाएँ संचालित हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका एवं बुनियादी ढाँचे से संबंधित योजनाएँ शामिल हैं।
2. **प्रभावशीलता सीमित है** - योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता अपेक्षाकृत सीमित है। 65.7% भील महिलाएँ इन योजनाओं से अनभिज्ञ हैं।
3. **जागरूकता सबसे बड़ी चुनौती** - योजनाओं की प्रभावशीलता में जागरूकता का अभाव सबसे बड़ी बाधा है। 66% महिलाएँ अपने क्षेत्र में संचालित योजनाओं का नाम तक नहीं जानतीं।
4. **सकारात्मक प्रभाव दिखे हैं** - JSY ने संस्थागत प्रसव में सुधार किया है; छात्रवृत्ति योजनाओं ने शिक्षा उपस्थिति बढ़ाई है; वन धन योजना ने आजीविका के नए अवसर प्रदान किए हैं।
5. **संरचनात्मक बाधाएँ कायम हैं** - भौगोलिक दुर्गमता, प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार एवं सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधक हैं।

7.2 सुझाव

7.2.1 नीतिगत सुझाव

1. **व्यापक जागरूकता अभियान** - भील जनजाति के बीच योजनाओं की जानकारी हेतु सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, विशेषकर महिलाओं एवं दूरस्थ क्षेत्रों में।
2. **एकीकृत सेवा वितरण** - विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक एकीकृत एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
3. **सांस्कृतिक संवेदनशीलता** - योजनाओं को भील जनजाति की सांस्कृतिक मान्यताओं एवं परंपराओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

4. **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग** - मोबाइल एप एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं की जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
5. **स्थानीय भाषा में सामग्री** - योजनाओं की जानकारी भील भाषा एवं स्थानीय बोलियों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
6. **नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन** - योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7.2.2 प्रशासनिक सुझाव

1. **क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय** - विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए।
2. **प्रशासनिक लेटलतीफी समाप्त** - योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक लेटलतीफी को समाप्त करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए।
3. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही** - योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

7.2.3 बुनियादी ढाँचा सुझाव

1. **सड़क एवं परिवहन** - दूरस्थ भील बस्तियों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण किया जाना चाहिए।
2. **विद्युतीकरण** - धरती आबा अभियान के तहत शेष बचे घरों तक विद्युत पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. **स्वास्थ्य केन्द्र** - दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।
4. **विद्यालय** - प्रत्येक भील बस्ती में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

8. शोध का महत्त्व

प्रस्तुत अध्ययन का महत्त्व निम्नलिखित है:

1. **शैक्षणिक महत्त्व** - यह अध्ययन भोपाल जिले के संदर्भ में भील जनजाति एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्संबंध पर उपलब्ध साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
2. **नीतिगत महत्त्व** - अध्ययन के निष्कर्ष एवं सुझाव नीति-निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक हैं, विशेषकर भोपाल जिले में जनजातीय कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु।
3. **प्रायोगिक महत्त्व** - अध्ययन क्रियान्वयन एजेंसियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है।
4. **सामाजिक महत्त्व** - अध्ययन भील जनजाति की वास्तविक स्थिति एवं आवश्यकताओं को उजागर करता है, जो सामाजिक न्याय एवं समानता की दिशा में सहायक है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

9. सन्दर्भ

1. Dubey, P., & Singh, P. (2025). मध्य प्रदेश राज्य में जनजातियों के कल्याण में शासकीय विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रभाव. *International Journal of Multidisciplinary Trends*, 7(11), 91-95.
2. वर्मा, सी., & गर्ग, डी. (2025). आरक्षण नीतियों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में भील जनजाति की महिलाओं की प्रगति का अध्ययन. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 7(4).
3. Government of Madhya Pradesh. (2026). आदिवासी क्षेत्रों के 63 हजार घरों में पहुंचेगी बिजली. *Dainik Bhaskar*, Bhopal.
4. Shodhganga. (n.d.). Chapter-VI: Impact of Capacity Building Programmes on Bhil Tribal Women's. *inflibnet.ac.in*.
5. IUSSP. (2012). *Janani Surakshya Yojana and its impact on Newborn Care among Bhil Tribe of Madhya Pradesh, India*. International Union for the Scientific Study of Population.
6. Government of India. (2021). *Census of India 2011: Primary Census Abstract*. Office of the Registrar General & Census Commissioner.
7. Government of India. (2024). धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. *Press Information Bureau*.
8. TRIFED. (n.d.). वनधन विकास योजना. *trifed.tribal.gov.in*.
9. Government of Madhya Pradesh. (n.d.). जनजातीय कार्य विभाग. *tribal.mp.gov.in*.